

503

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 23 अप्रैल, 2015

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट में गैस गोदाम की स्थापना हेतु कुल 0.200 है० भूमि कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल, उत्तराखण्ड को सशुल्क पट्टे पर हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1002/सात-30/2012-13 दि०-19.07.2014 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-3095/रा०प०-भू०हस्ता (गैस गो० कूँउप्रेती)/2014 दिनांक-09.09.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम कूँउप्रेती, तहसील गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ की गैर ज०वि० ख०खा० सं०-68 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खसरा सं०-2487/2701 मध्ये रकबा 0.060 है० तथा खसरा सं०-2490/2700 मध्ये रकबा 0.140 है० इस प्रकार कुल 0.200 है० भूमि को शासनादेश सं०-258/16(1)/73-राजस्व-1 दि०-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा०-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों/निगमों को वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य की दर से निकाले गये नजराने तथा मालगुजारी के 150 गुने के बराबर की धनराशि एकमुश्त वसूल कर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पट्टे पर सशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।
2. प्रश्नगत नॉन जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस०एल०पी०)/ (सी) संख्या-3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील सं०-436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि०-जनवरी, 2011 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में पर्यटन विभाग से संबंधित नियमों एवं दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

21

7. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
8. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
9. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
10. भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
11. संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)

सचिव।

पृ०प०सं०- 773 /संमदिनांकित/2015

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. महाप्रबन्धक, कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि०, ओक पार्क हाउस, नैनीताल।
5. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतोष बडोनी)

उप सचिव।